हिन्दी पाक्षिक समाचार पत्र

मारवाड़ का मित्र

HAPPY INDEPENDENCE DAY

RNI Reg No. RAJHIN/2003/10136 Post Reg No. RJ/SRO/9657/2023-25

www.marwadkamitra.in twitter.com/MARWADKAMITRA facebook.com/marwarkamitra/ youtube.com/c/mkmnewsnetwork

वर्ष 22 | अंक 16 | सांचौर, गुरुवार , 15, अगस्त 2024 | संस्थापक : स्व. श्री भगवानदास वैष्णव, | मूल्य वार्षिक 350 रुपये | कुल पृष्ठ - 4

समस्त पाठकों, विज्ञापनदाताओं एवं समस्त देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं

- संपादक / प्रकाशक

किसानों को सहकारी समितियों के मार्फत केंद्रीय सहकारी बैंकों से फसली ऋण लेने में हो रही परेशानी

सहकारी बैंको के लिए ऋण पॉलिसी तय नहीं कर पाया नाबार्ड

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर। केंद्रीय सहकारी बैंको के माध्यम से संचालित ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा अल्पकालीन फसली ऋण वितरण किया जा रहा हैं, मिली अपुष्ट जानकारी के मुताबिक, प्रदेश में पिछले 4 माह से राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानि नाबार्ड से ऋण की पॉलिसी तय नहीं होने के कारण, 29 केंद्रीय सहकारी बैंकों को अभी तक नाबार्ड से पुनर्वित्त नहीं मिला है, पुनर्वित्त का पैसा नहीं मिलने के कारण प्रदेश के किसानां को समय पर फसली सहकारी ऋण नहीं मिल रहा हैं, या फिर नाम मात्र का ऋण मिला है। जालोर एवं सांचौर जिले में फसली ऋण के लिए इस वित्तीय वर्ष में 7125 नए किसानों ने पंजीयन कराया हैं, लेकिन उनमें से महज 496 किसानों को 69 लाख रुपए का ही ऋण दिया हैं,

औसतन किसान को 15 हजार रुपए की ऋण राशि दी गई हैं, जबकि ऋण सीमा 1.5 लाख रुपए की है। वही, प्रदेश में 39.00 लाख किसान पंजीकृत हैं, जिसमें से 28.74 लाख किसानों को 11,197 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया है। जबकि किसानों की साख सीमा करीब 26 हजार करोड़ की हैं। यानी आधे से कम राशि किसानों को मिली है। यह ऋण बैंकों ने अपने संसाधनों से मुहैया कराया है। जबकि पॉलिसी अप्रैल में रिलीज होनी थी। ज्ञात रहे कि नाबार्ड की ओर से बैंकों को करीब 40 प्रतिशत ऋण राशि 4.7 प्रतिशत ब्याज पर तथा शेष राशि 7.75 प्रतिशत ब्याज पर मुहैया कराई जाती है। जबकि केंद्रीय सहकारी बैंक किसानों को 7 प्रतिशत ब्याज पर फसली ऋण मुहैया कराते हैं। इसमें 2 प्रतिशत ब्याज सहकारी समितियों को मिलता है। इसकी भरपाई राज्य और केंद्र से मिलने वाले अनुदान से होती है। लेकिन लंबे अरसे से करीब 650 करोड़ रुपए ब्याज अनुदान के बकाया हैं।

फसली ऋण लेने के नियम

योजना के तहत फसली ऋण की शुरुआत 25 हजार रुपए से की जाती है। इसके बाद हर साल तय अवधि में लोन चुकाने वाले किसानों को बैंकों की ओर अपनी वित्तीय सक्षमता के अनुपात में 5 या 10 फीसदी की दर से बढ़ाकर ऋण दिया जाता है। ये राशि साल में दो बार खरीफ व रबी सीजन के हिसाब से बढ़ाकर दी जाती है। योजना के तहत एक किसान अधिकत्तम 1.50 लाख तक का लोन ले सकता हैं ।

39 लाख किसानों का पंजीयन प्रदेश में

28.74 लाख किसानों को 11 हजार करोड़ रुपए का ऋण मुहैया

26 हजार करोड़ की साख सीमा किसानों की

10 लाख किसानों को नहीं मिला फसली ऋण

किसानों पर बकाया, व्यवस्थापकों की मनमर्जी से अटकी ऋण वसूली

केंद्रीय सहकारी बैंक जालोर द्वारा सीजनली वितरित अल्पकालीन फसली पेटे जिलेभर के किसानों पर 2019 से अब तक बकाया ऋण वसूली में निरंतर वृद्धि हो रही हैं, इस वित्तीय वर्ष में भी जीएसएस पर बैंक की चालू मांग के पेटे ऋण वसूली बकाया चल रही है। वसूली नहीं होने की दो वजह है, एक तो फसली ऋण बिना रहन और गारंटी के दिया जाता है, इसलिए किसानों पर सख्ती नहीं हो पाती, वहीं ऋण वसूली वाली सोसायटियों के व्यवस्थापक ऋण वसूली कार्य में हमेशा से ही शिथिलता बरत रहे है।

किसानों के प्रति सरकार व बैंकों का नकारात्मक रवैया

जिले के सहकारी साख आंदोलन से जुड़े सुत्रो का कहना है कि सरकारों और बैंकों का रवैया किसानों के प्रति नकारात्मक रहा है। केवल चुनाव के वक्त लाख-पचास हजार का ऋण माफ कर घडियाली आंसू बहाए जाते हैं।

राशि की उपलब्धता के आधार पर ऋण मुहैया कराया जा सका है। इसकी मुख्य वजह अभी तक नाबार्ड शार्ट टर्म लोन पॉलिसी जारी नहीं करना है।

- बैंक प्रबंधन, सीसीबी जालोर

किसानों को फसली ऋण उपलब्ध कराने पर 2 प्रतिशत सहकारी समितियों को ब्याज अनुदान मिलता हैं, इसकी भरपाई राज्य और केंद्र से मिलने वाले अनुदान से होती है, लेकिन लंबे अरसे से प्रदेशभर में करीब 650 करोड़ रुपए ब्याज अनुदान के बकाया हैं।

- रायमलराम नेहरा, जिला अध्यक्ष व्यवस्थापक यूनियन बाड़मेर

रबी सीजन के फसली ऋण चुकाने की अवधि अब 31 अगस्त

जयपुर । रबी सीजन 2023-24 में वितरित फसली ऋण अदायगी की तिथि को 30 जून से बढ़ाकर 31 अगस्त 2024 कर दिया गया है। सहकारिता विभाग संयुक्त शासन सचिव की ओर से पंजीयक सहकारी समितियां जयपुर को वित्तीय वर्ष 2023-24 में वितरित रबी ऋण की अंतिम देय तिथि 30 जून से बढ़ाकर 31 अगस्त या ऋण लेने की तिथि से 12 माह जो भी पहले हो, करने के क्रम में पत्र भेजा हैं, जिसके मुताबिक, रबी सीजन 2023-24 में वितरित फसली ऋण चुकाने की अवधि 2 माह बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी, वही 2 माह का ब्याज अनुदान केंद्रीय सहकारी बैंकों के संसाधनों से व्यय करने के निर्देश दिए गए है।

व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना

नॉमिनी को 10 लाख का चैक वितरित

बांसवाड़ा,। दी बांसवाड़ा सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. शाखा परतापुर के अन्तर्गत वजवाना लैम्पस द्वारा राज सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजनान्तर्गत लाभार्थी के नॉमिनी श्रीमती गीता पंचाल को राशि रू. 10.00 लाख का चैक वितरित किया गया। इस दौरान वरिष्ठ प्रबंधक कल्पेश कुमार जैन, ग्राम पंचायत सरपंच परतुलाल चरपोटा, लैम्पस अध्यक्ष धुलजी पाटीदार, जगजी पाटीदार, खेमजी पाटीदार एवं पदमजी पाटीदार, ऋण पर्यवेक्षक मदनलाल जी डामोर उपस्थित रहे। वरिष्ठ प्रबंधक एवं व्यवस्थापक महीपाल सिंह झाला ने सरकार द्वारा विभिन्न बीमा योजनाओं की जानकारी दी ।

रिक्त सीटों के लिए 16 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन

जालोर। वीर वीरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महा विद्यालय, जालोर में श्रेणीवार रिक्त रही सीटों के लिए पुन: ऑनलाइन आवेदन 16 अगस्त 2024 तक भरे जायेगे । प्राचार्य अर्जुन सिंह उज्ज्वल ने बताया कि ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी व एसटी के अभ्यर्थी 16 अगस्त तक आवेदन कर सकते है, अंतिम तिथि 24 अगस्त 2024 हैं।

मारवाड़ का मित्र
हिन्दी पाक्षिक समाचार पत्र

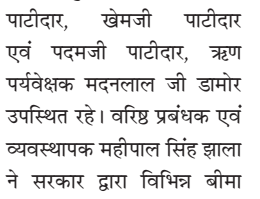

यदि आपको अपने क्षेत्र से लगाव है तो कृपया मारवाड़ का मित्र हिन्दी पाक्षिक समाचार पत्र के लिए मारवाड़ आंचल के विभिन्न धार्मिक, ऐतिहासिक कला,संस्कृति आदि अन्य सामाजिक,शैक्षणिक, व्यवसायिक स्थलों पर लेख,कथा, कहानी विवरण आदि हमें अवश्य प्रकाशनार्थ भिजवाने । प्रकाशन सामग्री के साथ संबंधित स्थल का फोटो भी एवं आपका फोटो भी अवश्य भिजवाएं । सामाजिक,शैक्षणिक, व्यवसायिक स्थलों पर लेख,कथा, कहानी विवरण आदि हमें अवश्य प्रकाशनार्थ भिजवाने । प्रकाशन सामग्री के साथ संबंधित स्थल का फोटो भी एवं आपका फोटो भी अवश्य भिजवाएं ।

-संपादक

राज्यपाल ने ली समीक्षा बैठक

कृषि, पशुपालन, सहकारिता से जुड़ी गतिविधियों को दिया जाए बढ़ावा

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर,। राज्यपाल श्री हरिभाऊ किसनराव बागडे ने प्रदेश में कृषि और पशुपालन से जुड़ी गतिविधियों में नवाचार अपनाते हुए अधिकाधिक लोगों को लाभान्वित किए जाने का आह्वान किया हैं। उन्होंने कृषि और सहकारिता क्षेत्र में राजस्थान को अग्रणी करने के लिए डेयरी से जुड़े उत्पादों में गुणवत्ता वृद्धि के साथ उनकी प्रभावी विपणन रणनीति पर भी कार्य किए जाने पर जोर दिया। राज्यपाल श्री बागडे ने राजभवन में राजस्थान में कृषि, पशुपालन और सहकारिता से जुड़े विभागों के अधिकारियों से इस क्षेत्र की गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने प्रदेश में प्राकृतिक खेती से जुड़े नए आयामों को अपनाने

राजभवन में विभिन्न गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी लेते हुए राज्यपाल

की आवश्यकता जताई। उन्होंने जैविक खेती और उद्यानिकी के लिए राजस्थान में हो रहे कार्यों के बारे में जानकारी लेते हुए कहा कि किसानों को नई फसलों और फलों की खेती के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों में अपनाई जा रही कृषि की अच्छी, महत्वपूर्ण और किसानों के लिए लाभकारी तकनीक को राजस्थान में भी उपयोग में लाया जाए। राज्यपाल श्री बागडे ने सहकारिता के अंतर्गत राज्य में दुग्ध उत्पादन गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने औसत दुग्ध संकलन, औसत तरल दुग्ध विपणन, पशु आहार उत्पादन, घी की आपूर्ति आदि के बारे में जानकारी लेते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में इन गतिविधियों से पशुपालकों को अधिकाधिक लाभान्वित किए जाने और नागरिक बैंक की संभावनाओं और सहकारिता क्षेत्र से जुड़े कार्यों से अधिकाधिक लोगों को जोड़कर कार्य करने की आवश्यकता जताई।

सभी जिलेवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

दुठवा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड दुठवा

पं. स. - चितलवाना, जिला - सांचौर

गंगाराम विश्नोई- अध्यक्ष

अपील ; समय पर फसली ऋण का चुकारा कर, आगामी फसल के लिए ब्याज मुक्त ऋण सुविधा का निरंतर लाभ प्राप्त करें। सोसाइटी और बैंक की प्रगति में भागीदार बनें।

देवाराम माली व्यवस्थापक

किसानों, ग्रामीणों,सहकारिता को समर्पित एक प्रगतिशील सहकारी सोसाइटी

सभी किसानों भाईयों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, कृष्णा जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं

सहकारिता का ध्येय वाक्य "एक सब के लिए, सब एक के लिए"

रणीसर ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड रणीसर

पूर्णतः कंप्यूटरीकृत एवं किसानों, ग्रामीणों,सहकारिता को समर्पित एक प्रगतिशील सहकारी सोसाइटी

कुलभानसिंह राठौड़ अध्यक्ष

अपील ; समय पर फसली ऋण का चुकारा कर, आगामी फसल के लिए ब्याज मुक्त ऋण सुविधा का निरंतर लाभ प्राप्त करें। सोसाइटी और बैंक की प्रगति में भागीदार बनें।

भवानीसिंह राठौड़ व्यवस्थापक

सभी जिलेवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

रायमलराम नेहरा - जिला अध्यक्ष
सहकारी समितियां व्यवस्थापक
यूनियन यूनिट बाड़मेर

सभी जिलेवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

पिचियाक ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड पिचियाक

पं. स. - बिलाड़ा, जिला - जोधपुर

गंगा सिंह - अध्यक्ष

राजेन्द्र सीरवी - उपाध्यक्ष

अपील ; समय पर फसली ऋण का चुकारा कर, आगामी फसल के लिए ब्याज मुक्त ऋण सुविधा का निरंतर लाभ प्राप्त करें। सोसाइटी और बैंक की प्रगति में भागीदार बनें।

सहदेव कीर व्यवस्थापक

सभी जिलेवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

चौपड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड चौपड़ा

पंचायत समिति - सोजत, जिला - पाली

भुण्डाराम सेवदा
व्यवस्थापक

सहकारिता का ध्येय वाक्य "एक सब के लिए, सब एक के लिए"

दुर्गाराम आशु - अध्यक्ष
मदनलाल पालीवाल - उपाध्यक्ष
विजयराज - स. व्यवस्थापक
अणदाराम - स. व्यवस्थापक
हीराराम - सैल्समैन

अपील ; समय पर फसली ऋण का चुकारा कर, आगामी फसल के लिए ब्याज मुक्त ऋण सुविधा का निरंतर लाभ प्राप्त करें। सोसाइटी और बैंक की प्रगति में भागीदार बनें।

पूर्णतः कंप्यूटरीकृत एवं किसानों, ग्रामीणों,सहकारिता को समर्पित एक प्रगतिशील सहकारी सोसाइटी

सहकारी बैंक कर्मचारियों एवं अधिकारियों को समर्पित अवकाश भुगतान करने की उठी मांग

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । प्रदेश में अपेक्स बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक, राज्य भूमि विकास बैंक एवं प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अप्रैल 2024 से नियमानुसार देय 15 दिवस समर्पित अवकाश का भुगतान करने की मांग सहकार नेता सूरजभानसिंह आमेरा ने उठाई है। इसके लिए ऑल राजस्थान को-ऑपरेटिव बैंक एपलाइज यूनियन व ऑल राजस्थान को-ऑपरेटिव बैंक

सहकार नेता ने कहा कि सहकारी बैंको में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित सहकारी विभाग के सभी अधिकारियों ने तो समर्पित अवकाश की सुविधा पेटे अप्रैल 2024 में ही पूरा भुगतान उठा लिया है, जबकि उसी बैंक के मूल सहकारी बैंक कार्मिक को नियमानुसार देय समर्पित अवकाश भुगतान अभी तक नहीं किया हैं,

ऑफिसर्स एसोसिएशन की ओर से सहकारिता मंत्री, सहकारिता विभाग के शासन सचिव सहित रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जयपुर को ज्ञापन देकर, नियमानुसार समर्पित अवकाश भुगतान की मांग की है। सहकार नेता ने बताया कि नियमानुसार वित्तीय वर्ष में सहकारी बैंक के लाभ में होने पर 15 दिवस समर्पित अवकाश बैंक कर्मचारी व अधिकारी को अप्रैल माह से 15 दिन के वेतन का नकद भुगतान किया जाता है, यह सुविधा वर्षों से देय है । उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पात्र सहकारी बैंको के लाभ में होने व अर्जित लाभ पर आयकर देने की मजबूत आर्थिक स्थिति के बावजूद अपेक्स बैंक, एसएलडीबी सहित पात्र सीसीबी एवं पीएलडीबी सहकारी बैंकों के कर्मचारियों व अधिकारियों को अप्रैल 2024 में मिलने वाले समर्पित अवकाश का भुगतान अगस्त माह तक नहीं किया गया है। जिससे राज्य भर के सहकारी बैंक कर्मियों में सरकार के प्रति असंतोष व रोष व्याप्त है, आमेरा ने कहा कि भुगतान की देरी से बैंक कर्मियों के उपार्जित अवकाश लेप्स होने से भी दोहरा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है ।

जिला स्तरीय जनसुनवाई व जन-अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक 16 को

जालोर। राज्य सरकार के निर्देशानुसार आमजन की परिवेदनाओं की सुनवाई एवं समस्याओं के त्वरित, गुणात्मक एवं सकारात्मक निराकरण के लिए व्यापक एकीकृत परिवाद निवारण प्रणाली "संपर्क समाधान" के तहत 16 अगस्त को प्रात: 11 बजे जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के भारत निर्माण सेवा केन्द्र पर वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से जिला स्तरीय जनसुनवाई एवं राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज परिवेदनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित कर आमजन की समस्याओं का समाधान कर उन्हें राहत प्रदान की जायेगी।

पैक्स कर्मचारी संघ प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मिलने का मांगा समय

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । प्रदेश में ग्राम सेवा सहकारी समितियों और केंद्रीय सहकारी बैंकों के मध्य बढ़ते असंतुलन और

फसली ऋण व्यवसाय पर देय ब्याज अनुदान का समय पर भुगतान नहीं होने का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है. राष्ट्रीय सहकारी पैक्स कर्मचारी संघ भारत के राष्ट्रीय महासचिव नीतेन्द्र कुमार शर्मा ने कहा हैं कि वित्त विभाग में लंबित कैडर पत्रावली के निस्तारण का मामला महामहिम राज्यपाल के समक्ष उठाने का फैसला किया है, और महामहिम राज्यपाल से मिलने का वक्त पत्र के जरिए मांगा है. महासचिव ने कहा कि, महामहिम राज्यपाल से आने वाले समय में मुलाकात का अवसर मिलने पर 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा सहकारी समितियों की सात सूत्री मांग के पूरे मामले से महामहिम राज्यपाल को अवगत कराया जाएगा । जिसमें, प्रदेश में हानी वाली सहकारी समितियों का अवसायन होने से बचाने के लिए वैद्यनाथ पैकेज की तर्ज पर अन्य सहायता पैकेज देने के साथ ही, प्रदेश की सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मियों की एकरुपता वेतन प्रणाली लागू करने, सहकारी समितियों में व्यवसाय विविधीकरण को लेकर एक कमेटी बनाकर, उसमें हानी वाली समितियों को लाभ में लाने के विषय पर चर्चा कर, कमेटी द्वारा दिए गए सुझाव की ठोस रुप से पालना करने के बारे में अवगत करवाया जाएगा ।

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

उथमण ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड उथमण

पं. स. - शिवगंज, जिला - सिरोही

किसानों, ग्रामीणों,सहकारिता को समर्पित एक प्रगतिशील सहकारी सोसाइटी

महेन्द्रसिंह देवड़ा - अध्यक्ष
रघुनाथसिंह देवड़ा - उपाध्यक्ष
देवाराम मीणा - व्यवस्थापक
अमर सिंह चौहान - क. ऑपरेटर

दलपतसिंह राठौड़
सहा. व्यवस्थापक

सरकार ने किसानों के लिए ब्याज सहायता योजना जारी रखने को दी मंजूरी

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

मुंबई। सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिए गए कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए 3 लाख रुपये तक के अल्पकालिक ऋणों के लिए ब्याज सहायता योजना जारी रखने को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत किसानों को 7 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर ऋण मिलता है। समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3 प्रतिशत प्रति वर्ष की अतिरिक्त ब्याज सहायता प्रदान की जाती है। आरबीआई ने कहा कि इसका यह भी अर्थ है कि उपरोक्त अनुसार समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 4 प्रतिशत प्रति

- सरकार ने किसानों को ब्याज दर के लिए सहायता देने की घोषणा की है।
- इसके तहत किसानों को 7 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर ऋण मिलता है।
- ऋण देने वाली संस्थाओं को ब्याज सहायता की दर 2024-25 के लिए 1.5 प्रतिशत

वर्ष की दर से अल्पकालिक फसल ऋण और/या पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन आदि सहित संबद्ध गतिविधियों के लिए अल्पकालिक ऋण मिलेगा।

एक परिपत्र में, रिजर्व बैंक ने कहा कि ऋण देने वाली संस्थाओं को ब्याज सहायता की दर 2024-25 के लिए 1.5 प्रतिशत होगी। इसमें कहा गया है कि फसल ऋण घटक की सीमा ब्याज छूट और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन लाभों के लिए प्राथमिकता लेगी और शेष राशि को पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन आदि सहित संबद्ध गतिविधियों के लिए माना जाएगा। किसानों द्वारा संकटपूर्ण बिक्री को हतोत्साहित करने और उन्हें अपने उत्पादों को गोदामों में संग्रहीत करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, केसीसी के तहत ब्याज छूट का लाभ फसल की कटाई के बाद छह महीने तक की अवधि के लिए छोटे और सीमांत किसानों को उपलब्ध होगा। आरबीआई परिपत्र में कहा गया है कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के लिए, उस वर्ष के लिए लागू ब्याज छूट दर पुनर्गठित ऋण राशि पर पहले वर्ष के लिए बैंकों को उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसे पुनर्गठित ऋणों पर दूसरे वर्ष से सामान्य ब्याज दर लागू होगी। संशोधित ब्याज छूट योजना के तहत किसानों को परेशानी मुक्त लाभ सुनिश्चित करने के लिए, 2024-25 में उपर्युक्त अल्पकालिक ऋणों का लाभ उठाने के लिए आधार लिंकेज अनिवार्य बना रहेगा।

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

पूर्णतः कंप्यूटरीकृत एवं किसानों, ग्रामीणों,सहकारिता को समर्पित एक प्रगतिशील सहकारी सोसाइटी

रामस्वरुप अध्यक्ष

अपील ; समय पर फसली ऋण का चुकारा कर, आगामी फसल के लिए ब्याज मुक्त ऋण सुविधा का निरंतर लाभ प्राप्त करें। सोसाइटी और बैंक की प्रगति में भागीदार बनें।

वासुदेव पंचारिया व्यवस्थापक

सहकारिता का ध्येय वाक्य "एक सब के लिए, सब एक के लिए"

रड़कपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड रड़कपुरा

आवास योजना का विस्तार

प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे चरण के तहत आगामी पांच वर्षों में तीन करोड़ घरों का निर्माण होगा, जिनमें दो करोड़ आवास ग्रामीण क्षेत्रों में तथा एक करोड़ आवास शहरी क्षेत्र में होंगे. इस निर्णय पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है. इस चरण में केंद्र सरकार द्वारा लगभग 4.35 ट्रिलियन रुपये खर्च किये जायेंगे. शहरी गरीब एवं मध्य वर्गीय परिवारों के आवास पर कुल निवेश 10 ट्रिलियन रुपये होने का अनुमान है, जिसमें सरकार 2.3 ट्रिलियन रुपये का अनुदान देगी. ग्रामीण आवासों पर केंद्र और राज्य सरकारें 3,06,137 करोड़ रुपये खर्च करेंगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यालय के प्रारंभ में ही ग्रामीण भारत के हर परिवार के लिए आवास उपलब्ध कराने को अपनी प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल किया था. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की शुरुआत अप्रैल, 2016 में की गयी थी, जिसके तहत मार्च, 2024 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ 2.95 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया था. शहरी क्षेत्र में आवास मुहैया कराने की योजना जून, 2015 में प्रारंभ की गयी थी. अनुदान और सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के साथ-साथ निर्माण को बढ़ावा देने पर आधारित इस योजना से अब तक करोड़ों परिवारों को लाभ पहुंचा है. प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे चरण में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न और मध्य वर्ग के वैसे सभी परिवार आवेदन कर सकते हैं, जिनके पास देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं है. शहरी क्षेत्र में तो किराये पर पक्का मकान लेने के लिए भी योग्य आवेदकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है. रोटी, कपड़ा और मकान मनुष्य की बुनियादी जरूरतें हैं. हमारे देश में आबादी का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है, जो मकान बना पाने की स्थिति में नहीं है. हालांकि पहले भी केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा आवास मुहैया कराने या सस्ती दरों पर कर्ज की व्यवस्था कराने के प्रयास पहले भी होते रहे हैं, पर प्रधानमंत्री आवास योजना अपने लक्ष्य एवं उपलब्धि में अग्रणी है. घर का सपना पूरा होना महज एक सपने का साकार होना ही नहीं है, यह परिवार के लिए एक उपलब्धि और उत्साह का आधार होता है, जो उसे उत्तरोत्तर प्रगति के लिए प्रेरित करता है. बीते वर्षों में आवास के अलावा अनाज, रसोई गैस, बिजली, चिकित्सा आदि के लिए भी अनेक कल्याण योजनाएं शुरू की गयी हैं, जैसे आयुष्मान भारत योजना, निशुल्क राशन, बिजली में छूट, उज्ज्वला योजना आदि. ऐसी योजनाओं ने गरीब और निम्न आय वर्गीय परिवारों की मुख्य चिंताओं का काफी हद तक समाधान किया है, जिससे वे अपने जीवन को बेहतर बनाने की ओर अग्रसर हुए हैं. आवास योजना के विस्तार से बड़ी संख्या में घर बनने से सीमेंट, लोहा आदि अनेक उद्योगों को भी लाभ होगा तथा रोजगार सृजन में भी मदद मिलेगी.

आज़ादी के बाद के सबक

-डॉ. सत्यवान सौरभ
(कवि,स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार,
आकाशवाणी एवं टीवी पेनालिस्ट,)

> आज़ादी के बाद सबसे महत्वपूर्ण सबक यह है कि भारत को विकसित बनाने के लिए हमें पांच प्रमुख क्षेत्रों में पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम करने की जरूरत है। इनमें कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, शिक्षा व स्वास्थ्य सुरक्षा, सूचना व संचार तकनीक, भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक पॉवर, महत्वपूर्ण तकनीक में आत्मनिर्भरता। ये पांचों क्षेत्र एक-दूसरे से जुड़े तो हैं ही, एक-दूसरे पर प्रभाव भी डालते हैं। इसलिए इनमें बेहतर सामंजस्य होना चाहिए। यह देश की आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बहुत जरूरी है। इसके साथ ही हममें यह सकारात्मक सोच भी होनी चाहिए कि हम कुछ नया अविष्कार करके ही अपने देश में अच्छा बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि विज्ञान और तकनीक से ही मानव कल्याण, शांति और खुशहाली आ सकती है।

भारत ने वैश्विक पहचान हासिल करने के लिए ढेर सारी चुनौतियों को पार करते हुए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक बनने के लिए छोटे कदम उठाए। भारत ने आजादी के बाद से एक लंबा सफर तय किया है, कई सही और गलत फैसलों से परहेज किया है, जो कई ऐसे स्थलों को पीछे छोड़ता है जो विभाजन की पीड़ा से एक मजबूत, शक्तिशाली और विकासशील राष्ट्र की यात्रा को परिभाषित करते हैं। हाल ही के दशकों में भारत धीरे-धीरे अंतरराष्ट्रीय स्थान पर ऊपर चढ़ता जा रहा है और इसके कारण विश्व की एक प्रमुख महाशक्ति के रूप में इसका वैश्विक प्रभाव भी नजर आने लगा है. पिछले चार दशकों में एक जबरदस्त ताकत के रूप में उभरकर सामने आया है और भारत ने भी काफ़ी ऊँचाइयाँ हासिल कर ली हैं. इसके कारण विश्व की आर्थिक शक्ति का केंद्र यूरोप और उत्तरी अमेरिका से हटकर एशिया की ओर स्थानांतरित होने लगा है. उदीयमान प्रबल शक्ति के बावजूद भारत अक्सर वैचारिक ऊहापोह में घिरा रहता है. यही कारण है कि देश के उज्ज्वल भविष्य और वास्तविकता में अंतर दिखाई देता है. हालांकि भारत महाशक्ति बनने की प्रक्रिया में प्रमुख बिंदुओं पर खरा उतरता है, लेकिन व्यापक अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में घरेलू मुद्दों के कारण वह कमजोर पड़ जाता है. हालांकि भारत के कई नेता गति को आगे बढ़ाने और सामाजिक राजनीतिक संकट से बचने में विफल रहे, यह भी राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्रतिबद्धता की कमी का मामला था। भारत में विविधता के कारण, कहीं न कहीं आना मुश्किल है। हालांकि, अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) यानी एक समान नागरिक संहिता लगने के प्रयासों को रूढ़िवादी वर्गों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने दावा किया कि इससे सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा होगा। पानी की तरह किलोमीटर पर भारत में भाषा बदल जाती है। इसलिए,हिंदी केवल आधिकारिक भाषा के रूप में लाना मुश्किल था और 1965 में तमिलनाडु के हिंदी-विरोधी आंदोलन जैसे हिंसा और गरमागरम बहस देखी गई। जनसंख्या नियंत्रण कानून 2019 का जनसंख्या नियंत्रण विधेयक, जिसे 2022 में वापस ले लिया गया था। दो संतान नीति को आजादी के बाद से 35 बार संसद में पेश किया गया है। इन मसौदे की आम जनता द्वारा भारी आलोचना की गई थी। कृषि अर्थशास्त्री और अन्य हितधारक दशकों से कृषि बाजार में सुधार की वकालत कर रहे हैं। इसने संकट से बचने के लिए तीन प्रमुख कृषि सुधार कानून जिन्हें निरस्त कर दिया गया को फिर से चुपके मोड में आगे बढ़ाने के बारे में सरकार को झिझक दिया। लेबर कोड पर नियम आज तक टाले गए। कोड के परिणामस्वरूप कम टेक-होम पे और आसान छंटनी होगी। नि:संदेह सरकार को सुधार के मार्ग पर बहुत सावधानी से चलना होगा। लोकतंत्र की सफलता में पहला है मतदान को अनिवार्य बनाना, जैसा कि कम से कम 30 लोकतंत्रों में किया गया है, जिससे मतदान प्रतिशत बढ़कर 90 प्रतिशत से अधिक हो गया है। वर्तमान में, भारत में मतदान प्रतिशत कम है। आईपीसी की धारा 124ए का घोर दुरुपयोग एक उपहास है लेकिन अधिकांश राजनीतिक दल नहीं चाहते कि कानून के इस प्रावधान को हटाया जाए। सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम के लिए राज्य सशस्त्र पुलिस और केंद्रीय अर्ध-सैन्य पुलिस का उपयोग करना चाहिए। घुसपैठ, भाड़े के सैनिकों, आतंकवादियों और आतंकवादियों से निपटने के लिए जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के नागरिक क्षेत्रों से सशस्त्र बलों को अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास ले जाने के लिए अधिनियम को हटाना एक मजबूत मामला है। राजनीतिक हस्तक्षेप और पुलिस जांच में अपर्याप्तता को देखते हुए, भारत ने औपनिवेशिक काल से यूरोप में प्रचलित जिज्ञासु प्रणाली में आरोप लगाने वाली प्रणाली से एक संरचनात्मक परिवर्तन करने का समय आ गया है। जस्टिस वी.एस. मलीमथ ने रिफॉर्म ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर अपनी रिपोर्ट में भी इसका सुझाव दिया है। जीएम खाद्य फसलों के लिए भारत अभी भी आनुवंशिक रूप से इंजीनियर या आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव (जीएम) फसलों पर अनिर्णीत है। राजनीतिक इच्छा देश की खाद्य सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी सहित एक आधुनिक कृषि नीति ढांचे को अपनाने और लागू करने की कमी है। राजनीतिक प्रतिष्ठान ने राजनीतिक कार्यकर्ता आंदोलन से खुद को बचा लिया है। भारत में सामाजिक राजनीतिक अशांति के बावजूद नेताओं द्वारा कई कठोर निर्णय सुधार किए गए जैसे 1991 के सुधारों के दौरान नेताओं की राजनीतिक इच्छाशक्ति को याद रखना चाहिए। हम उस नेतृत्व की सराहना करते हैं जिसने भारत को च्चट्टान से गिरनेज्ज से बचाया और भुगतान संकट के आसन्न संकट के साथ फंड और बैंक की मजबूरी के तहत सुधारों का प्रबंधन किया। 1960 में भारत में हरित क्रांति ने गेहूं और दालों की अधिक उपज देने वाली किस्मों के विकास के साथ खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि देखी। 1976 सामूहिक नसबंदी अभियान संजय गांधी द्वारा शुरू किया गया था और एक वर्ष में लगभग 6.2 मिलियन पुरुषों की नसबंदी की गई थी, जिसमें लगभग 2000 लोग सर्जरी के कारण मारे गए थे। 1990 वीपी सिंह सरकार द्वारा कुछ जातियों को जन्म के आधार आरक्षण पर सरकारी नौकरी देने के विरोध में पूरा देश विरोध की चपेट में था, बावजूद इसके निर्णय जारी रहा। भारत ने 1998 में पोखरण में परमाणु बम परीक्षण किए, ऑपरेशन शक्ति कोडनेम के साथ निरस्त्रीकरण के वैश्विक दबाव में कठोर निर्णय लिया। इसने भारत को एक पूर्ण परमाणु राष्ट्र बना दिया। 2016 में, सरकार ने 500 रुपये और 1,000 रुपये के नोटों के विमुद्रीकरण की घोषणा की।

कई किसान, व्यापारी और युवा वर्ग सभी आंदोलन कर रहे थे लेकिन काले धन के खिलाफ एक कदम के रूप में इसे आगे बढ़ाया गया माल और सेवा कर; यह प्रमुख केंद्रीय और राज्य करों को शामिल करने के बाद परिणामी कर था। कश्मीर की पहेली सुलझाना राज्य के पूर्ण एकीकरण के लिए अनुच्छेद 370 का निरस्तीकरण लंबे समय से लंबित था और इसे जम्मू-कश्मीर की स्थिति पर सीधे रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए सालों पहले किया जाना चाहिए था। आज़ादी के बाद सबसे महत्वपूर्ण सबक यह है कि सुधारों की प्रक्रिया को अधिक परामर्शी, अधिक पारदर्शी और संभावित लाभार्थियों को बेहतर ढंग से संप्रेषित किया जाना है। यह समावेशिता ही है जो भारत के लोकतांत्रिक कामकाज के केंद्र में है। हमारे समाज की तर्कशील प्रकृति को देखते हुए, सुधारों को लागू करने में समय और विनम्रता लगती है। लेकिन ऐसा करना सुनिश्चित करता है कि हर कोई जीत जाए। भारत को विकसित बनाने के लिए हमें पांच प्रमुख क्षेत्रों में पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम करने की जरूरत है।

(यह लेखक के अपने विचार हैं)

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं
झूंगरी ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड झूंगरी
पंचायत समिति-चितलवाना, जिला - सांचौर
दीपाराम चौधरी अध्यक्ष
श्रीराम विश्नोई उपाध्यक्ष
पूर्णतः कंप्यूटरीकृत एवं किसानों, ग्रामीणों,सहकारिता को समर्पित एक प्रगतिशील सहकारी सोसाइटी
अपील ; समय पर फसली ऋण का चुकारा कर, आगामी फसल के लिए ब्याज मुक्त ऋण सुविधा का निरंतर लाभ प्राप्त करें। सोसाइटी और बैंक की प्रगति में भागीदार बनें।
लिखमाराम जाखड़
व्यवस्थापक

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं
केरिया ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड केरिया
पंचायत समिति-चितलवाना, जिला - सांचौर
किसानों, ग्रामीणों,सहकारिता को समर्पित एक प्रगतिशील सहकारी सोसाइटी
भगवानाराम विश्नोई- अध्यक्ष
अपील ; समय पर फसली ऋण का चुकारा कर, आगामी फसल के लिए ब्याज मुक्त ऋण सुविधा का निरंतर लाभ प्राप्त करें।
रामस्वरुप विश्नोई व्यवस्थापक

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं
गुड़ा हेमा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड गुड़ा हेमा
पंचायत समिति-चितलवाना, जिला - सांचौर
किसानों, ग्रामीणों,सहकारिता को समर्पित एक प्रगतिशील सहकारी सोसाइटी
रुगनाथ विश्नोई अध्यक्ष
अपील ; समय पर फसली ऋण का चुकारा कर, आगामी फसल के लिए ब्याज मुक्त ऋण सुविधा का निरंतर लाभ प्राप्त करें।
दिनेश विश्नोई व्यवस्थापक

प्राकृतिक कारणों से खराब हुई फसल पूरी तरह कवर होती है

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

नई दिल्ली । पूर्ववर्ती फसल बीमा योजनाओं में कई तरह की कठिनाइयां थीं, पहले की सरकारों में कई सारी फसल बीमा योजनाएं थीं, अपर्याप्त दावे थे, बीमित राशि कम मिलती थी, दावों के निपटान में बिलंब होता था। किसानों और किसान संगठनों को कई तरह की आपत्तियां थीं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में फसल बीमा संबंधी प्रश्नों के उत्तर देते हुए कहा कि मुझे यह कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री नई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेकर आए। पहले, फसल बीमा के लिए 3 करोड़ 51 लाख आवेदन आते थे और अब 8 करोड़ 69 लाख आवेदन आए हैं, वहीं सकल बीमित राशि बढ़कर 2.71 लाख करोड़ रूपये से ज्यादा हो गई है। 32 हजार 404 करोड़ रु. प्रीमियम किसानों ने दिया है और इसके बदले उन्हें 1.64 लाख करोड़ रूपये क्लेम दिया गया है। केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्राकृतिक कारणों से अगर फसल खराब होती है तो वो भी पूरी कवर होती है और किसान को उसका लाभ मिलता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पुरानी फसल बीमा के अनुसार, बैंक के ऋणी का बीमा आवश्यक रूप से किया जाता था और बीमे की प्रीमियम की राशि को बैंक स्वयं ही काट लेता था। सरकार ने यह विसंगति दूर कर योजना को स्वैच्छिक बना दिया है। अब तक 5 लाख 1 हजार हेक्टेयर क्षेत्र इसमें कवर हुआ है, जो 2023 में बढ़कर 5 लाख 98 हजार हेक्टेयर हो गया है, 3 करोड़ 57 लाख किसान कवर हुए हैं। सरकार ने योजना को सरल बनाने के लिए कई उपाय किए हैं, ताकि योजनाओं का लाभ लेने में किसान को परेशानी ना हो। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा के 3 अलग-अलग मॉडल हैं। केंद्र सरकार सिर्फ पॉलिसी बनाती है। राज्य सरकार जिस मॉडल को चुनना चाहे, उस मॉडल को चुनती है। मॉडल चुनने के बाद बीमा कंपनियां (निजी क्षेत्र व सार्वजनिक क्षेत्र) प्रतिस्पर्धी दरों पर फसल बीमा योजना लागू करने का काम करती है। फसल बीमा योजना हर राज्य के लिए आवश्यक नहीं है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पूरे देश के हर जिले के लिए है। योजना की इकाई में पहले कभी विसंगतियां होती थी कि ब्लॉक को ही इकाई बना दिया जाता था। अब ग्राम पंचायत को इकाई बनाया गया है, ताकि ग्राम पंचायत में किसान का नुकसान हो तो किसान के नुकसान की भरपाई सही से की जा सके। पहले की योजनाओं की कमियों को दूर किया गया है। साथ ही, हर ग्राम पंचायत में कम से कम 4 क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट करना भी आवश्यक कर दिया है। राज्य सरकार से उपज डाटा उपलब्ध होने के महीने के अन्दर दावे की गणना की जाती है। केंद्र सरकार पॉलिसी बनाती है तो उसे सही से लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। उन दावों के भुगतान में देर होती है तो एक प्रावधान किया गया है कि अगर बीमा कंपनी देर करेगी तो उस पर 12 प्रतिशत की पेनल्टी लगेगी, जो कि सीधे किसान के खाते में डाली जाएगी। उन्होंने कहा कि जब हमने बीमा भुगतान के देरी के कारणों को देखा तो 98.5 प्रतिशत कारण राज्य सरकारों द्वारा अपने हिस्से की प्रीमियम राशि को देर से जारी करना है। मैं राज्य सरकारों से निवेदन करना चाहूंगा कि वह अपनी तरफ से प्रीमियम की राशि जारी करने में देर ना करें, कुछ मामलों में बीमा कंपिनयों और राज्य सरकारों के बीच विवाद होता है, कई बार किसानों के नम्बर ग़लत होते हैं, इन कारणों से भी देरी होती है। श्री चौहान ने कहा कि इसी खरीफ सीजन से 12 प्रतिशत की पेनल्टी लगाकर सीधे किसान के खाते में भुगतान का काम होगा।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पुरानी फसल बीमा के अनुसार, बैंक के ऋणी का बीमा आवश्यक रूप से किया जाता था और बीमे की प्रीमियम की राशि को बैंक स्वयं ही काट लेता था। सरकार ने यह विसंगति दूर कर योजना को स्वैच्छिक बना दिया है।

फसल बीमा योजना ; बीमा के नियम शर्तों की जानकारी न होने से किसानों को उठाना पड़ता है नुकसान

बीमा के नियम और शर्तों की पहेली में उलझे किसान

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

बांसवाड़ा. फसल खराबा होने पर किसानों को राहत देने के लिए शुरू की गई फसल बीमा की सुविधा तकलीफदेय हो गई है। बीमा क्लेम के मापदंड क्या हैं ? क्या सावधानी बरतनी है ? आदि बारीकियां किसानों लिए आज भी पहेली है। इस कारण ही फसल खराबे के बाद कई किसान क्लेम न मिलने पर दर-दर भटक रहे हैं। इसका खामियाजा निरक्षर और कम पढ़े लिखे किसानों को ज्यादा भुगतना पड़ता है। बीमा के नियम शर्तों की पेंचीदगियों से अंजान ये किसान अच्छे की आस में बीमा राशि देकर बीमा धारक तो बन जाते हैं, पर खराबे के बाद राहत नहीं मिल पाती। किसानों को संबल देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें भरसक प्रयास करती नजर आती हैं और बीमा राशि का 98 फीसदी दोनों सरकारों के द्वारा आधा-आधा दिया भी जाता है, किसानों को किश्त के रूप में बीमा राशि का महज दो प्रतिशत ही भुगतान देना पड़ता है। विभाग अनदेखी से किसानों को हमेशा से

सोयाबीन फसल

ही नियम शर्तों में उलझकर नुकसान उठाना पड़ता है। हालांकि कृषि विभाग किसानों की जागरूकता का लगातार दावा करता आया है और इस वर्ष भी बीमा नियमों में बदलावों से अवगत कराने के लिए फसल बीमा पाठशाला लगाने की बात कही गई। इतना ही नहीं 20 जून से 18 जुलाई तक लगाई गई इन पाठशालाओं में 40 हजार किसानों के जुडने का भी विभाग दावा कर रहा है। विभाग के ये दावे जमीनी स्तर पर कितने प्रभावशाली हैं इसे जानने के लिए जब पत्रिका टीम ने जिले के कई किसानों से बात की तो कृषक इनकी बारीकियों से अंजान नजर आए। वहीं, किसान प्रतिनिधि भी किसानों को लाभ न मिलने और नियम शर्तों से अंजान होने की बात कह रहे हैं।

इस बार बदले नियम किसान अंजान

50 वर्षों से खेती कर रहे और मैट्रिक तक पढ़े बालावाड़ा के दीप सिंह बताते हैं कि किसानों को बीमा से जुड़ी कोई जानकारी नहीं रहती है। नियम शर्तें भी काफी उलझी हुई होती हैं। इन्हें स्पष्ट करने के भी प्रयास नहीं होते हैं। इसका खामियाजा किसान को भुगतना पड़ता है। इस बीमा में जनरल क्लेम ही दिया जाना है। व्यक्तिगत क्लेम का प्रावधान नियमों में नहीं रखा गया है।

ऋणी और अऋणी किसानों के लिए बीमा कराने के अलग तरीके

बता दें कि किसानों का बीमा दो प्रकार से होता है। पहला वे किसान जिन्होंने ऋण ले रखा और दूसरे वे जिन्होंने फसली ऋण नहीं लिया है। ऋण लेने वालों को 'लोनी फॉर्मर' और लोन न लेने वालों को 'नॉन लोनी फॉर्मर' कहा जाता है। लोनी फॉर्मर का बीमा राशि सीधे खाते से काटी जाती है। कितनी होती है बीमा राशि ये भी नहीं पता किसानों ने बताया कि उन्हें सिर्फ यह पता होता है कि बीमा के लिए उनकी इतनी राशि काटी गई है। लेकिन किसी प्रकार काटी गई है, उसके मापदंड क्या है ? खेत की कुल कितनी राशि बनी इसकी कोई जानकारी उन्हें नहीं होती।

किसानों को पता ही नहीं फसल बदलने पर देनी होती है सूचना

किसान संघ प्रतिनिधि बताते हैं कि सीजन की फसल में बदलाव करने पर बीमा धारक किसानों को जानकारी देनी होती है, तभी नुकसान पर बीमा का लाभ मिलता है। लेकिन किसानों को यह बात पता न होने पर किसान फसल बुवाई में किए गए बदलाव की जानकारी नहीं देते और खराबा होने पर वे मुआवजे की शर्तों में नहीं आते। वे कहते हैं कि सिर्फ यही नहीं फसल कटाई प्रयोग से पूर्व भी किसानों को अवगत नहीं कराया जाता है।

इन 6 फसलों पर यह है बीमित राशि

बीमित राशि (प्रति है.)	कृषक प्री. (% में)	कृषक प्री. (रुपए में)
मक्का 33145	2%	663
अरहर 53439	2%	1067
उड़द 41684	2%	834
कपास 34980	5%	1749
धान 24191	2%	484
सोयाबीन 52633	2%	1053

(विभाग से प्राप्त जानकारी के आधार पर)

कैंप लगाकर दी जानकारी

पूर्व में किसानों को बीमा लाभ को लेकर दिक्कतों को लेकर जिला प्रशासन के निर्देश पर इस बार पंचायत स्तर तक कैंप लगाकर जानकारी दी गई। इसमें सभी ऋणी किसानों और अन्य किसानों को भी जोड़ा गया। अन्य विभाग का भी सहयोग लिया गया। हमारी ओर से पूरे प्रयास किए गए हैं, ताकि किसानों को समस्या न आए।

-दलीप सिंह, संयुक्त निदेशक, कृषि विस्तार, बांसवाड़ा

सभी जिलेवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं
ईटादा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड ईटादा
पं. स. - चितलवाना, जिला - सांचौर
किसानों, ग्रामीणों,सहकारिता को समर्पित एक प्रगतिशील सहकारी सोसाइटी
महेंद्र कुमार - अध्यक्ष
अपील ; समय पर फसली ऋण का चुकारा कर, आगामी फसल के लिए ब्याज मुक्त ऋण सुविधा का निरंतर लाभ प्राप्त करें। सोसाइटी और बैंक की प्रगति में भागीदार बनें।
कनीदास वैष्णव व्यवस्थापक

सभी जिलेवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं
बिठुड़ा पिरोन ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड बिठुड़ा पिरोन
पं. स. सुमेरपुर, जिला -पाली
अपील ; समय पर फसली ऋण का चुकारा कर, आगामी फसल के लिए ब्याज मुक्त ऋण सुविधा का निरंतर लाभ प्राप्त करें। सोसाइटी और बैंक की प्रगति में भागीदार बनें।
ढलाराम सरगरा अध्यक्ष
जब्बरसिंह भाटी व्यवस्थापक

बैंकिंग नियमन कानून में संशोधन संबंधी विधेयक पेश

चार व्यक्तियों को बना सकते हैं बैंक खाते का नॉमिनी

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

- निवेशकों को मिलेगा बिना दावे वाला लाभांश, शेयर या बांड्स पर देय ब्याज वापस पाने का अधिकार
- सभी सहकारी बैंकों को पखवाड़े के आखिरी शुक्रवार के बजाय अंतिम दिन भेजनी होगी वैधानिक रिपोर्ट

नई दिल्ली। आने वाले दिनों में देश का हर बैंक ग्राहक अपने बैंक खाते के लिए चार नॉमिनी नामित कर सकता है। एक साथ चार व्यक्तियों को भी बैंक खाते के लिए अपने बाद उत्तराधिकारी घोषित किया जा सकता है या फिर क्रमवार तरीके से भी इनका नाम कानूनी तरीके से दर्ज कराया जा सकता है। इस संबंध में लोकसभा में सरकार की तरफ से पेश बैंकिंग (संशोधन) कानून, 2024 में प्रस्ताव किया गया है। विधेयक वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पेश किया। इसके जरिए बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े चार अलग-अलग तरह के कानूनों में संशोधन किया जा रहा है।

सरकार का कहना है कि संशोधन से बैंकिंग ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा ज्यादा बेहतर तरीके से की जा सकेगी। एक अहम प्रस्तावित संशोधन यह है कि अगर किसी निवेशक का अन्कलेम्ड लाभांश, शेयर या बांड्स पर देय ब्याज निवेशक सुरक्षा कोष में हस्तांतरित किया जा चुका है तो उक्त निवेशक को अपनी राशि वापस लेने का हक होगा। कई बार निवेशकों को पता नहीं चलता है और पुराने निवेशित राशि बैंक खाता संचालित नहीं होने की वजह से निवेशक शिक्षा व सुरक्षा कोष (आईईएसएफ) में डाल दिया जाता है। एक बार उक्त फंड में पैसा जाने के बाद उससे निकालने की व्यवस्था नहीं थी जिसकी राह अब खोल दी जाएगी। सरकार की तरफ संशोधन विधेयक के प्रस्तावना में कहा गया है कि विगत कुछ वर्षों में देश के बैंकिंग सेक्टर में कई तरह के बदलाव हुए हैं और उनके हिसाब से कदम उठाते हुए संशोधन के प्रस्ताव किये जा रहे हैं।

छोटे-मोटे बदलाव के लिए विधेयक क्या जरुरत ; कांग्रेसी सांसद मनीष तिवारी, टीएमसी सांसद सौगत राय व कुछ दूसरे विपक्षी सांसदों ने प्रस्तावित संशोधन विधेयक का यह कहते हुए विरोध किया कि सरकार इनके जरिए सहकारी बैंकों में अपना हस्तक्षेप बढ़ाने की मंशा रखती है। राय ने यह कहा कि इन छोटे-मोटे बदलाव के लिए संसद में विधेयक पेश करने की जरूरत ही नहीं थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनका जबाव देते हुए सरकार की मंशा सहकारी बैंकों में हस्तक्षेप की नहीं बल्कि उनके काम काज को बेहतर बनाने और बैंकों को ज्यादा आजादी देने की है।

सहकारी बैंकों के कामकाज में होगा सुधार

कुछ संशोधन सहकारी बैंकों के काम काज को बेहतर करने के उद्देश्य से किये जा रहे हैं। मसलन, सहकारी बैंकों के निदेशकों के कार्यकाल की सीमा 8 वर्ष से बढ़ा कर 10 वर्ष किया जा रहा है। इसमें पूर्णकालिक निदेशक या चेयरमैन को शामिल नहीं किया गया है। अन्य वाणिज्यिक बैंकों के लिए यह व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है। इसी तरह से केंद्रीय सहकारी बैंकों के निदेशक पद पर कार्यरत व्यक्तियों को साथ-साथ राज्यों के सहकारी बैंकों के निदेशक के तौर पर भी काम करने की इजाजत देने का प्रस्ताव है। सभी बैंकों के लिए एक व्यवस्था यह की जा रही है कि अब उन्हें हर पखवाड़े के अंतिम नहीं बल्कि पखवाड़े के अंतिम दिन वैधानिक रिपोर्ट भेजनी होगी।

सभी किसानों भाईयों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन
कृष्णा जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं
सहकारिता का ध्येय वाक्य "एक सब के लिए, सब एक के लिए"
सेलड़ी ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड सेलड़ी
पंचायत समिति - आहोर,, जिला - जालोर
पूर्णतः कंप्यूटरीकृत एवं किसानों, ग्रामीणों,सहकारिता को समर्पित एक प्रगतिशील सहकारी सोसाइटी
अमरसिंह जोधा - अध्यक्ष
दलपतसिंह - उपाध्यक्ष
अपील ; समय पर फसली ऋण का चुकारा कर, आगामी फसल के लिए ब्याज मुक्त ऋण सुविधा का निरंतर लाभ प्राप्त करें। सोसाइटी और बैंक की प्रगति में भागीदार बनें।
तेजसिंह राजपुरोहित
व्यवस्थापक

किसान क्रेडिट कार्ड में दर्ज फसल में कृषक कर सकते हैं परिवर्तन - उद्योग राज्य मंत्री

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

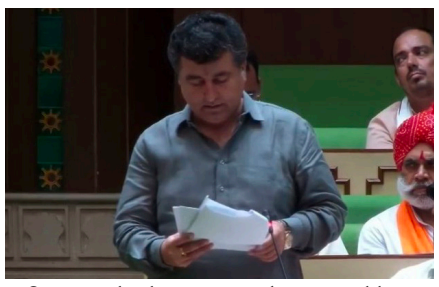

विधानसभा में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए उद्योग राज्य मंत्री के.के. विश्नोई

- 31 जुलाई है खरीफ फसल के लिए बीमा की अंतिम तिथि
- 29 जुलाई तक कृषक दर्ज फसल में कर सकता है परिवर्तन
- 31 दिसबर है रबी फसल के लिए बीमा की अंतिम तिथि
- 29 दिसबर तक कृषक दर्ज फसल में कर सकता है परिवर्तन

जयपुर,। उद्योग राज्य मंत्री श्री केके विश्नोई ने विधानसभा में कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड में कृषक द्वारा दर्ज कराई गई फसल का बीमा बैंकों के माध्यम से किया जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसान द्वारा उल्लेखित फसल से भिन्न फसल बोने पर किसान इसकी सूचना अंतिम तिथि से 2 दिन पहले तक अद्यतन कर सकता है। उन्होंने जानकारी दी कि खरीफ की फसल के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई है। कृषक दर्ज फसल में 29 जुलाई तक परिवर्तन कर सकता है। इसी प्रकार रबी की फसल के लिए अंतिम तिथि 31 दिसम्बर है। कृषक द्वारा 29 दिसम्बर तक दर्ज फसल में परिवर्तन किया जा सकता है। उद्योग राज्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का कृषि मंत्री की ओर से जवाब दे रहे थे। उन्होंने आश्वस्त किया कि सिवाना विधानसभा क्षेत्र की तहसीलों में खरीफ 2023 का बीमा क्लेम वितरण शीघ्र किया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि सिवाना विधानसभा क्षेत्र में खरीफ 2023 में 16.17 करोड रूपये का बीमा क्लेम आंकलित हुआ है। जिसमें से 7.12 करोड रूपये का बीमा क्लेम जारी हो चुका है एवं 9.04 करोड रूपये का बीमा क्लेम पोर्टल के माध्यम से वितरणाधीन है। इससे पहले विधायक श्री हमीर सिंह भायल के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उद्योग राज्य मंत्री ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र सिवाना के किसानों का खरीफ 2019 से निरंतर दोनों फसल मौसम सत्रों के लिये फसल बीमा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंण्डिया द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि फसल बीमा योजनांतर्गत दर्ज की गई उपज क्षति के आधार पर सिवाना विधानसभा क्षेत्र में खरीफ 2019 से खरीफ 2023 के लिये 2.14 लाख फसल बीमा पॉलिसी धारक पात्र किसानों को 87.97 करोड रू के बीमा क्लेम का भुगतान बीमा कंपनियों द्वारा जारी किया गया है। श्री विश्नोई ने बताया कि खरीफ 2019 से रबी 2022-23 तक के लिये नेफ्ट बाउन्स एवं खाता सत्यापित ना होने के कारण राशि 1.94 करोड के बीमा क्लेम लंबित हैं, जिसके लिये केन्द्र सरकार से प्राप्त निर्देशों के क्र म में वैकल्पिक खातों में बीमा क्लेम वितरित करने हेतु बीमा कंपनियों को निर्दिष्ट किया गया है।

सभी जिलेवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं
मालगढ ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.
पंचायत समिति - आहोर,, जिला - जालोर
अपील ; समय पर फसली ऋण का चुकारा कर, आगामी फसल के लिए ब्याज मुक्त ऋण सुविधा का निरंतर लाभ प्राप्त करें। सोसाइटी और बैंक की प्रगति में भागीदार बनें।
पूर्णतः कंप्यूटरीकृत एवं किसानों, ग्रामीणों,सहकारिता को समर्पित एक प्रगतिशील सहकारी सोसाइटी
रुपसिंह राजपुरोहित
अध्यक्ष
लक्ष्मणसिंह राजपुरोहित
व्यवस्थापक

अल्पावधि ऋण कम ब्याज पर उपलब्ध कराने को कहा

नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा संशोधित ब्याज सहायता योजना जारी रखने के निर्णय को देखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से फसल ऋण, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन सहित संबंधित गतिविधियों के लिए कम ब्याज दर पर अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराने को कहा है। किसानों को 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर 3 लाख रुपये की सीमित राशि दी जाएगी।

सभी जिलेवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं
बुढ़तरा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड बुढ़तरा
पंचायत समिति - आहोर,, जिला - जालोर
अपील ; समय पर फसली ऋण का चुकारा कर, आगामी फसल के लिए ब्याज मुक्त ऋण सुविधा का निरंतर लाभ प्राप्त करें। सोसाइटी और बैंक की प्रगति में भागीदार बनें।
लक्ष्मणसिंह राठौड़ अध्यक्ष
जुजाराम देवासी व्यवस्थापक
किसानों, ग्रामीणों एवं सहकारिता को समर्पित एक प्रगतिशील सहकारी सोसाइटी

हरियाली तीज पर अपेक्स बैंक परिसर में किया वृक्षारोपण

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान एक पेड़ माँ के नाम एवं राज्य सरकार के हरियालो राजस्थान अभियान के तहत प्रदेशभर में सात करोड़ वृक्ष लगाने के क्रम में हरियाली तीज के अवसर पर दी राजस्थान स्टेट को-आपरेटिव बैंक टोंक रोड़ जयपुर प्रधान कार्यालय में वृक्षारोपण किया गया । इस दौरान बैंक प्रधान कार्यालय परिसर में प्रबंध निदेशक संजय पाठक, सहकार नेता सूरज भान सिंह आमेरा, नाबार्ड उप महाप्रबंधक देशराज मौर्य, बैंक महाप्रबंधक संदीप खंडेलवाल, उप महाप्रबंधक राकेश शर्मा ने आंवला एवं बील पत्र के पौधे लगाकर बैंक की समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की, इसके साथ ही अपेक्स बैंक कर्मचारियों एवं अधिकारियों की उत्साह पूर्वक भागीदारी रही ।

सभी किसानों भाईयों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन
कृष्णा जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं
नरेन्द्रसिंह बालोत
अध्यक्ष
विक्रमसिंह बालोत
उपाध्यक्ष
एवं समस्त संचालक मण्डल सदस्य गण
अपील ; समय पर फसली ऋण का चुकारा कर, आगामी फसल के लिए ब्याज मुक्त ऋण सुविधा का निरंतर लाभ प्राप्त करें। सोसाइटी और बैंक की प्रगति में भागीदार बनें।
भागीरथसिंह राजावत
व्यवस्थापक
पावटा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड पावटा
पंचायत समिति - आहोर,, जिला - जालोर
पूर्णतः कंप्यूटरीकृत, किसानों, ग्रामीणों, सहकारिता को समर्पित एक प्रगतिशील सहकारी सोसाइटी

देश में कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए नई योजना

नई दिल्ली। कोयला मंत्रालय ने वैश्विक खनन ऑपरेटरों के माध्यम से देश में कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। मंत्रालय ने कहा है कि इस योजना का लक्ष्य खनन संचालन को सुव्यवस्थित करके लागत कम करना तथा कोयला उत्पादन में वृद्धि करना है। इन ऑपरेटरों को कोयले का खनन कर इसे कोल इंडिया लिमिटेड तक पहुंचाने का काम सौंपा गया है। न ऑपरेटरों का चयन खुली वैश्विक निविदाओं के माध्यम से किया गया था। समझौते के अनुसार ऑपरेटर उत्खनन से लेकर कोयले की डिलीवरी तक पूरी खनन की निगरानी करेंगे।

सभी किसानों भाईयों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन
कृष्णा जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं
मूलगिरी गोस्वामी
अध्यक्ष
सिकन्दर खोखर
सहा. व्यवस्थापक
एवं समस्त संचालक मण्डल सदस्य गण
अपील ; समय पर फसली ऋण का चुकारा कर, आगामी फसल के लिए ब्याज मुक्त ऋण सुविधा का निरंतर लाभ प्राप्त करें। सोसाइटी और बैंक की प्रगति में भागीदार बनें।
नारायणलाल मेघवाल
व्यवस्थापक
बिठुड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड बिठुड़ा
पंचायत समिति - आहोर,, जिला - जालोर
पूर्णतः कंप्यूटरीकृत, किसानों, ग्रामीणों, सहकारिता को समर्पित एक प्रगतिशील सहकारी सोसाइटी

गांवों को गरीबी से मुक्त करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध

नई दिल्ली। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार गांवों को गरीबी से मुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने लोगों को कौशल प्रदान करने और क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने हैदराबाद में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान की आम परिषद की बैठक के बाद अधिकारियों और छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामीण विकास सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों और गांवों को सड़क संपर्क, पेयजल और बिजली आपूर्ति प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि रोजगार उपलब्ध कराना ग्रामीण विकास की कुंजी है और देश की 10 करोड़ महिलाओं ने अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए कौशल हासिल किया है। उन्होंने कहा कि गरीबी मुक्त गांव उनका सपना है।

सभी किसानों भाईयों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन
कृष्णा जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं
(जिले की अ-श्रेणी में चयनित सर्वश्रेष्ठ सहकारी समिति)
सियाणा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड सियाणा
पंचायत समिति - जालोर, जिला - जालोर
(किसानों, ग्रामीणों एवं सहकारिता को समर्पित एक प्रगतिशील सहकारी सोसाइटी)
हमारी सेवाएं :
मिनी बैंक की मियादी जमाओं पर ब्याज दर देय सुविधा ।
अल्पावधि फसली सहकारी ऋण, भूमि की उपलब्धता के आधार पर स्वीकृत साख सीमा के तहत बायोमेट्रिक पद्धति से वितरित
झूरसिंह राठौड़ - उपाध्यक्ष
धाराराम लुकड़ा - व्यवस्थापक
नरपतसिंह चौहान - स. व्यवस्थापक
प्रकाशसिंह राव - स. व्यवस्थापक
प्रागाराम - सलाहकार
गंगाराम सरगरा - सहा. कर्मचारी
सहकारिता का ध्येय वाक्य "एक सब के लिए, सब एक के लिए"
प्रदीपसिंह चौहान
अध्यक्ष

केवीएसएस एवं भंडार कर्मियों की सेवा स्थायी कर नियमित वेतनमान भुगतान की उठी मांग

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

केवीएसएस एवं उपभोक्ता भंडारों कार्मिकों संयुक्त बैठक संपन्न

सहकार नेता के नेतृत्व में दिया जाएगा ज्ञापन

बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर निर्णय लिया गया कि सहकार नेता सूरजभानसिंह आमेरा के नेतृत्व में सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार, शासन सचिव सहित सहकारिता मंत्री को ज्ञापन देकर सहकारिता में केवीएसएस व उपभोक्ता भंडार संस्थाओं के कर्मियों के साथ सहकारिता फ़िलोसॉफ़ी के विपरीत व्याप्त भेदभाव, मनमानीपूर्ण कार्य शैली, विधि सम्मत जायज काम को लंबित करना व लटकाकर कर्मियों को परेशान करने की हक़ीक़त पर ध्यान आकृष्ट किया जाएगा, सहकार नेता ने मांग रखी कि इन समस्त कर्मियों को प्रोबेशन अवधि पूर्ण होने की तारीख़ से स्थायी कर नियमित वेतन भुगतान लागू किया जाए, साथ ही, सभी भंडार एवं केवीएसएस कर्मियों की समरूप सेवा शर्त वेतनमान सुविधाएँ व परीलाभ लागू किए जाए ।

जयपुर । राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड के माध्यम से वर्ष 2021 में क्रय-विक्रय सहकारी समिति एवं सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार में 385 पदों पर सीधी भर्ती में सफल नियोजित कार्मिको की एक महत्वपूर्ण बैठक अशोक कुमार पोटलिया डूंगरगढ़, सुरेश कुमार जैसलमेर एवं उमा चौधरी भीलवाड़ा की संयुक्त अध्यक्षता में सम्पन्न हुई । इस बैठक में सहकार नेता सूरजभानसिंह आमेरा की मुख्य उपस्थिती में भी रही । रविवार को आयोजित बैठक में विभिन्न जिलों से उपस्थित केवीएसएस एवं उपभोक्ता भंडारों कार्मिकों ने एक स्वर में अपने प्रोबेशन अवधि के 2 वर्ष नवम्बर 2023 में पूर्ण हो जाने के बावजुद सेवा स्थायीकरण आदेश जारी नहीं कर, नियमित वेतनमान भुगतान नहीं करने की मनमानीपूर्ण स्थिति पर विरोध व्यक्त किया, वही, कार्मिकों ने बताया कि सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार को बार-बार ज्ञापन देने व मिलने के उपरांत भी प्रोबेशन अवधि पूर्ण हो जाने के 7 माह बाद भी अपेक्षित कंप्यूटर परीक्षा लेकर स्थायीकरण के आदेश जारी नहीं किए जाने पर समस्त कार्मिक हैरान व परेशान हैं । इस दौरान सहकार नेता सूरज भान सिंह आमेरा ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि माननीय उच्च न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों के तहत किसी भी कार्मिक की प्रोबेशन अवधि पूर्ण हो जाने के अगले दिन तक नियोक्ता द्वारा किसी भी प्रकार का अन्यथा असंतोष संदेश, नोटिस व स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है, तो वह कार्मिक स्वत: स्थायी मान लिया जाता है, सहकार नेता ने बताया कि केवीएसएस व उपभोक्ता भंडार में कर्मियों की प्रोबेशन अवधि नवंबर 2023 में ही पूरे हुए आज 7 माह व्यतीत हो गये है, तो यह सभी कार्मिक विधिक निर्णय के तहत स्थायी मानकर नियमित वेतन के हकदार है, उदयपुर संभाग के विभिन्न भंडार व केवीएसएस में प्रबंधन नियोक्ता द्वारा इसी आधार पर नवंबर में ही स्थायीकरण आदेश जारी कर नियमित वेतन भुगतान लागू कर दिया है, लेकिन राज्य के अधिकांश भंडार व समितियों में कंप्यूटर परीक्षा की आड़ में अभी तक उन्हें फिक्स पारिश्रमिक ही दिया जा रहा है , रजिस्ट्रार के लिखित निर्देश के बावजूद कंप्यूटर परीक्षा विभाग द्वारा नहीं ली जा रही है, एक ही भर्ती में आए एक ही सहकारी विभाग में भंडार व केवीएसएस में कार्यरत कर्मियों के साथ दोहरे मापदंड भेदभाव, अन्याय व शोषण किया जा रहा है । इस दौरान राज्य की क्रय विक्रय सहकारी समितियों व उपभोक्ता भंडार में लंबे समय से पीड़ित व परेशान कर्मचारियों ने बड़ी संख्या मे भाग लिया, बैठक को जोधपुर संभाग से समीर ख़ान, बीकानेर संभाग अशोक कुमार पोटलिया, भरतपुर संभाग से राजेश कुमार मीणा, जयपुर संभाग से धर्मवीर सैनी, अजमेर संभाग से संजय जैन, कोटा संभाग से रामदेव सेवलिया, विजय सिंह भाटी, उमा चौधरी, राजेश यादव, निर्मल शेखावत, कुलदीप जोशी, मदन मोहन जांगीड व प्रकाश छीपा ने भी संबोधित किया, वही, बैठक में जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, बीकानेर, चूरु, झुनझुनूँ, गंगानगर, हनुमानगढ़, अजमेर, अलवर, भरतपुर, जयपुर, दौसा, करौली, टोंक, कोटा, बाँरा, भीलवाड़ा जिले से केवीएसएस एवं भंडार कर्मी मौजूद रहें ।

घर बैठे मारवाड़ का मित्र मंगाने के लिए भर कर भेजें
सदस्यता फॉर्म
मारवाड़ का मित्र हिंदी पाक्षिक मारवाड़ आंचल का प्रमुख पाक्षिक समाचार पत्र हैं । समाचार पत्र में कृषि पशुपालन, सहकारिता, ग्रामीण विकास से जुड़ी अहम खबरों का प्रकाशन कर पाठकों तक अखबार की प्रति प्रेषण कर रहा है। मारवाड़ का मित्र समय-समय पर भिन्न-भिन्न विषयों पर विशेषांक का प्रकाशन भी करता है तथा अपने ग्राहकों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के भेजता है ।
अतः मुझे / हमें भी अंग्राकित पते पर मारवाड़ का मित्र समाचार पत्र की प्रति डाक द्वारा भेजें ।
सदस्यता राशि
☐ एक वर्ष रु. 350/- ☐ दो वर्ष रु. 700/- ☐ तीन वर्ष रु. 1050/- ☐ छह वर्ष रु. 2100/-
डाक से नियमित रूप से इस पते पर मारवाड़ का मित्र भेजने के लिए DD / मनीआर्डर मारवाड़ का मित्र के नाम भेज रहा हूं ।
नाम / संस्था का नाम.....
ग्राम..... पोस्ट.....
तहसील..... जिला.....
फोन..... पिन कोड.....
राशि (रुपए) ..... बैंक का नाम.....
अगर आप किसी कारण से भुगतान नहीं कर पा रहे हैं तो सीधे हमारे बैंक अकाउंट में पैसे भेजें. अगर आप सीधे बैंक ट्रांसफर कर रहे हैं तो Marwadkamitra@gmail.com पर अपना पूरा नाम, फोन नंबर, भुगतान की राशि और Transaction id हमें मेल करें ताकि हम आपका व्यक्तिगत तौर पर आभार प्रकट कर सकें.
Bank Account Details :
Name: Marwad ka Mitra
A/C No.: 11134027554
IFSC Code: RMGB0000134
Google / Phonepay
9602473302
सदस्यता हेतु लिखें ➤ मारवाड़ का मित्र हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र
संपादकीय/व्यवस्थापक कार्यालय - वैष्णव फार्म परावा,
तहसील-चितलवाना जिला-जालोर 343041
Mo. 9602473302, Visit Us:Marwadkamitra.in

मारवाड़ का मित्र
हिन्दी पाक्षिक समाचार पत्र
सांचौर, गुरुवार, 15 अगस्त 2024
4
RNI Reg. No - RAJHIN/2003/10136
Post Reg No. R.J./SRO/9657/2023-25

67,009 पैक्स के कप्यूटरीकरण के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान - शाह

पैक्स को 25 से अधिक व्यावसायिक गतिविधियों को शुरू करके अपनी व्यावसायिक गतिविधियों में विविधता लाने में मिलेगी सहायता

पैक्स के कप्यूटरीकरण परियोजना के लिए राष्ट्रीय स्तर का कॉमन सॉटवेयर नाबार्ड द्वारा विकसित किया गया है

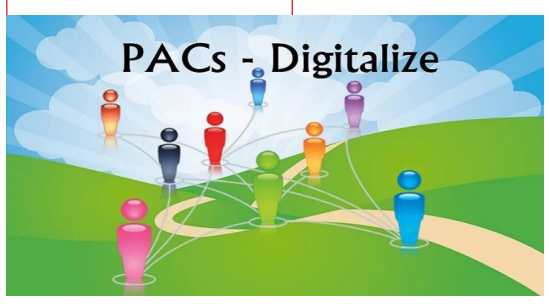

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

नई दिल्ली । भारत सरकार 2,516 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ कार्यात्मक पैक्स के कम्प्यूटरीकरण के लिए परियोजना को कार्यान्वित कर रही है, जिसमें सभी कार्यात्मक पैक्स को ईआरपी (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) आधारित कॉमन नेशनल सॉफ्टवेयर पर लाना, उन्हें राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) के माध्यम से नाबार्ड से जोड़ना शामिल है। यह जानकारी केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में देते हुए बताया कि इस परियोजना के लिए राष्ट्रीय स्तर का कॉमन सॉफ्टवेयर नाबार्ड द्वारा विकसित किया गया है और 21.07.2024 तक 27 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 25,904 पैक्स को ईआरपी सॉफ्टवेयर पर शामिल किया गया है। पैक्स की व्यवहारिकता बढ़ाने और उन्हें पंचायत स्तर पर जीवंत आर्थिक इकाई बनाने के लिए उनकी व्यावसायिक गतिविधियों में विविधता लाने के लिए, सभी हितधारकों के परामर्श के बाद सरकार द्वारा पैक्स के लिए मॉडल उपनियम तैयार किए गए हैं, इससे पैक्स को 25 से अधिक व्यावसायिक गतिविधियों को शुरू करके अपनी व्यावसायिक गतिविधियों में विविधता लाने में सहायता मिलेगी, जिसमें डेयरी, मत्स्य पालन, फूलों की खेती, गोदामों की स्थापना, खाद्यान्न, उर्वरक, बीज एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल वितरण, अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋण, कस्टम हायरिंग सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर, उचित मूल्य की दुकानें (एफपीएस), सामुदायिक सिंचाई, व्यवसाय संवाददाता गतिविधियां आदि शामिल हैं। मॉडल उपनियमों को अपनाकर, पीएसीएस ग्रामीण क्षेत्रों में सदस्य किसानों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने वाले बहु-सेवा केंद्रों के रूप में काम करने में सक्षम होंगे। वे पैक्स की परिचालन दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार करने में सहायता करेंगे; किसान सदस्यों को कृषि ऋण और विभिन्न गैर-ऋण सेवाएं प्रदान करके उन्हें आय के अतिरिक्त स्रोत प्रदान करेंगे।

पैक्स के कामकाज में बढ़ेगी विश्वसनीयता

ईआरपी (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) आधारित कॉमन नेशनल सॉफ्टवेयर, कॉमन अकाउंटिंग सिस्टम (सीएएस) और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (एमआईएस) के माध्यम से पैक्स के प्रदर्शन में दक्षता लाता है। इसके अलावा, पीएसीएस में प्रशासन और पारदर्शिता में भी सुधार होता है, जिससे ऋणों का तेजी से वितरण, लेन-देन की लागत में कमी, भुगतान में असंतुलन में कमी, डीसीबीबी और एसटीसीबी के साथ निर्बाध लेखा-जोखा होता है। यह किसानों के बीच पैक्स के कामकाज में विश्वसनीयता बढ़ाएगा और इस प्रकार सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को साकार करने में योगदान देगा।

पैक्स से जुड़े हुए है 13 करोड़ से अधिक किसान सदस्य

लगभग 1.05 लाख पैक्स से 13 करोड़ से अधिक किसान सदस्य जुड़े हुए हैं। यह परियोजना किसानों को अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक ऋण सुविधाओं तक पहुंच बढ़ाती है। इसके अलावा, पैक्स का कम्प्यूटरीकरण भी किसानों को पैक्स स्तर पर ही इन सेवाओं को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, जैसा कि पैक्स के लिए मॉडल उप-नियमों के तहत उल्लिखित विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए विभिन्न मॉड्यूल को शामिल करके किया गया है। यह पैक्स की आर्थिक गतिविधियों के विविधीकरण में भी मदद करता है, जिससे किसान सदस्यों को आय के अतिरिक्त और स्थायी स्रोत प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।

654.23 करोड़ रुपये की राशि जारी जारी

पैक्स के कम्प्यूटरीकरण परियोजना का उद्देश्य पैक्स के लिए मॉडल उप-नियमों के अंतर्गत निर्धारित 25 से अधिक आर्थिक गतिविधियों के लिए एक व्यापक ईआरपी समाधान प्रदान करना है, जिसमें विभिन्न मॉड्यूल जैसे कि अल्पकालिक, मध्यम और दीर्घकालिक ऋणों के लिए वित्तीय सेवाएं, खरीद संचालन, सार्वजनिक वितरण दुकानें (पीडीएस) संचालन, व्यवसाय नियोजन, भंडारण, बिक्री, उधार, परिसंपत्ति प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन आदि शामिल हैं। अब तक, 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से 67,009 पैक्स के कम्प्यूटरीकरण के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके लिए संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को भारत सरकार के हिस्से के रूप में 654.23 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

सभी किसानों भाईयों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन कृष्णा जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं

सहकारिता का ध्येय वाक्य "एक सब के लिए, सब एक के लिए"

आलवाड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड आलवाड़ा

पंचायत समिति - सायला, जिला - जालोर

जेठाराम व्यवस्थापक

दुर्जन सिंह
अध्यक्ष
मानाराम
उपाध्यक्ष
एवं समस्त संचालक मण्डल सदस्य गण

अपील ; समय पर फसली ऋण का चुकारा कर, आगामी फसल के लिए ब्याज मुक्त ऋण सुविधा का निरंतर लाभ प्राप्त करें। सोसाइटी और बैंक की प्रगति में भागीदार बनें।

पूर्णतः कंप्यूटरीकृत, किसानों, ग्रामीणों, सहकारिता को समर्पित एक प्रगतिशील सहकारी सोसाइटी

फसल खराबे का नहीं मिला मुआवजा, किसानों का प्रदर्शन

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

पाली. रोहट तहसील के किसानों को बीमा कपनी की ओर से वर्ष 2023 में हुए खराबे का मुआवजा अब तक नहीं दिया गया है। इस वर्ष एक सप्ताह पहले हुई बरसात से खेतों में फिर फसल खराब हो गई। इससे किसानों पर आर्थिक संकट गहराया हुआ है। किसानों ने कृषि विभाग परिसर में एकत्रित होकर नाराजगी जताई। कलक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। जिला कलक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर पिछले वर्ष का क्लेम दिलवाने व इस वर्ष खराबे की गिरदावरी कराने का आग्रह किया। **खेतों में भर गया पानी ;** वर्ष 2024 में मानसून की अत्यधिक बारिश के कारण खेतों में जल भराव हो गया। फसलें पानी में डूब गई। कई किसानों के मवेशियों की मौत हो गई। किसानों के घर टूट गए। किसानों ने स्पेशल गिरदावरी करवाकर वर्ष 2024 की भी बीमा राशि एवं मुआवजा दिलवाने की मांग की। गई। फसल व मकान आदि का मुआवजा दिलवाने का आग्रह किया।

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

अपना धन अपना बैंक अपना जिला

दी जालोर सैण्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
जालोर, शाखा - भीनमाल, जिला - जालोर

- आवास ऋण
- व्यक्तिगत ऋण
- डेयरी ऋण
- वाहन ऋण
- स्वयं सहायता समूह ऋण
- सहकार किसान कल्याण ऋण
- कम्पोकजट/इन्टीग्रेटेड ऋण
- कृषक मित्र
- किसान सबल योजना

अटूट रिश्ता विश्वास का
हर आवश्यकताओं के अनुरुप जमा व ऋण योजनाएं, जीवन बनाएं बेहतर सभी प्रकार के कृषि व अकृषि ऋण

श्री ओमपालसिंह भाटी प्रबन्ध निदेशक
श्री योगेश कुमार शर्मा शाखा प्रबंधक

अधिक जानकारी हेतु हमारी शाखा में संपर्क करें

सहकारी कर्मचारी संघ की नीमकाथाना एवं सीकर जिला स्तरीय कार्यकारिणी का गठन

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

सीकर । केंद्रीय सहकारी बैंक के कार्यक्षेत्र में संचालित ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्यरत कार्मिकों की एक मीटिंग का आयोजन राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ की जिला स्तरीय कार्यकारिणी का गठन हुआ, जिसमें अमरसिंह जीतरवाल नाथूसर को नीमकानाथा जिला अध्यक्ष एवं दुर्गासिंह सुंडा को सीकर जिला अध्यक्ष निर्वाचित किया, वही, दोनो जिला कार्यकारिणी में संयुक्त रुप से महादेवसिंह ऐचरा को सरंक्षक बनाया गया, इसके अलावा, एक जिला संघर्ष समिति का भी गठन किया गया हैं, जिसमें सतीश कुमार को अध्यक्ष, दुर्गासिंह सुंडा एवं अमरसिंह जीतरवाल को सदस्य, वही, समस्त शाखाओं के शाखा अध्यक्ष को संघर्ष समिति का सदस्य भी बनाया गया है, जो केंद्रीय सहकारी बैंक सीकर से जिला स्तरीय मांगों को लेकर संघर्ष करेंगी ।

कर्मचारी संघ जयपुर के निवर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष महादेवसिंह ऐचरा की अध्यक्षता में खाटू श्याम जी की नगरी में स्थित ग्राम सेवा सहकारी समिति परिसर में किया गया, इस दौरान सीकर एवं नीमकाथाना जिले में राजस्थान सहकारी

अस्सी हजार रुपए की घूस लेते हेड कांस्टेबल गिरफ्तार

नागौर. भ्रष्टाचार निरोधक यूरो (एसीबी), नागौर की टीम ने एक होटल संचालक के खिलाफ दर्ज मुकदमे में मदद के नाम पर अस्सी हजार रुपए की घूस लेते सदर थाने के हेड कांस्टेबल जालम सिंह को गिरफ्तार किया है। एसीबी की एएसपी कल्पना सोलंकी ने बताया कि परिवादी ने इस संबंध में शिकायत की थी किकुछ दिन पहले एक कपल के उनके होटल में रुकने के बाद बखेड़ा हो गया था। युवती ने आरोपी के खिलाफ सदर थाने में बलात्कार का मामला दर्ज करा दिया। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि वहां के रजिस्टर की एंट्री में काट-छांट हैं।

सेवानिवृत्त होने पर ऋण पर्यवेक्षक को दी गई भावभीनी विदाई, जताया आभार

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

सिरोही। केंद्रीय सहकारी बैंक की रेवदर शाखा में ऋण पर्यवेक्षक बाल कृष्ण वैष्णव के सेवानिवृत्त होने पर अनादरा-रेवदर हाईवे स्थित लुणोल टोल प्लाजा के पास वेड़ेश्वर मामाजी धाम पर विदाई समारोह का आयोजन कर उन्हें भावभीनी विदाई दी गई, इस विदाई समारोह के दौरान रेवदर एवं मंडार शाखा अंतर्गत संचालित पैक्स-लैम्पस कर्मियों सहित राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ जिला इकाई सिरोही जिला अध्यक्ष जसवंतसिंह राणावत, संरक्षक नरपतसिंह चारण ने श्री वैष्णव को साफा व माला पहनाकर सम्मानित किया । इस दौरान सीसीबी शाखा रेवदर के कार्यवाहक ऋण पर्यवेक्षक थानसिंह ईन्दा एवं सीसीबी शाखा अनादरा के कार्यवाहक ऋण

सीसीबी ऋण पर्यवेक्षक बाल कृष्ण वैष्णव की सेवानिवृत्ती पर विदाई देते हुए पैक्स-लैंपस कर्मी

पर्यवेक्षक विक्रमसिंह देवड़ा ने कहा कि किसी भी क्षेत्र में सरकारी कर्मी को एक दिन सेवानिवृत्त होना सुनिश्चित होता है। उन्होंने ऋण पर्यवेक्षक बालकृष्ण वैष्णव की प्रशंसा करते हुए कहा कि इनका कार्यकाल काफी सराहनीय रहा है। इनके सेवानिवृत्त होने से हम लोगों को इनकी कमी खलेगी। वहीं, सेवानिवृत्त ऋण पर्यवेक्षक वैष्णव ने कहा कि मुझे रेवदर एवं मंडार शाखा अंतर्गत संचालित पैक्स-लैम्पस कर्मियों सहित समिति संचालक बोर्ड सदस्यों की ओर से ढ़ेर सारा प्यार और स्नेह मिला है। जिसे मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा। इस दौरान केसरसिंह देवड़ा, वागसिंह देवड़ा, ताराराम, रमजान खान, लाखाराम, रुड़ाराम देवासी, चेलाराम राणा, भूताराम सहित रेवदर एवं मंडार शाखा के पैक्स-लैम्पस कर्मी मौजूद रहें ।

सभी किसानों भाईयों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन कृष्णा जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं

राजीवनगर ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड राजीवनगर

मांगीलाल विश्नोई व्यवस्थापक

प. स. - सांचौर, जिला - सांचौर
राजूराम
अध्यक्ष
एवं समस्त संचालक मण्डल सदस्य गण

अपील ; समय पर फसली ऋण का चुकारा कर, आगामी फसल के लिए ब्याज मुक्त ऋण सुविधा का निरंतर लाभ प्राप्त करें। सोसाइटी और बैंक की प्रगति में भागीदार बनें।

कोटा नागरिक सहकारी बैंक की बॉम बैठक का आयोजन

कोटा ; कोटा नागरिक सहकारी बैंक की बोम की बैठक रावतभाटा रोड स्थित प्रधान कार्यालय में अध्यक्ष राजेश बिरला की अध्यक्षता में हुई। प्रबंध संचालक बिजेन्द्र शर्मा ने बताया कि बैठक में सीआरआर व एसएलआर की अनुपालना, ऋण पॉलिसी 2024, सेगमेंट, साइबर सिक्योरिटी, जमाओं की समीक्षा, एनपीए वसूली, बैंक ग्राहक सेवा, सुरक्षा व्यवस्था, इंटरब्रांच व बैंक रिकन्सिलेशन, समीक्षा व प्रतिभूति निवेश सहित 20 बिंदुओं के एजेंडे पर बोर्ड व बोम सदस्यों के साथ विचार विमर्श किया। उन्होंने बताया कि बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया कि आमसभा का आयोजन 15 सितंबर को झालावाड़ स्थित माहेश्वरी भवन में किया जाएगा। बैठक में बोर्ड उपाध्यक्ष हेमराज सिंह हाड़ा, संचालक राकेश जैन, महेंद्र कुमार शर्मा आदि मौजूद रहे।

सभी किसानों भाईयों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन कृष्णा जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं

पमाणा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड पमाणा

तेजाराम देवासी व्यवस्थापक

प. स. - सांचौर, जिला - सांचौर
चोपाराम
अध्यक्ष
एवं समस्त संचालक मण्डल सदस्य गण

अपील ; समय पर फसली ऋण का चुकारा कर, आगामी फसल के लिए ब्याज मुक्त ऋण सुविधा का निरंतर लाभ प्राप्त करें। सोसाइटी और बैंक की प्रगति में भागीदार बनें।

कृषकों को उन्नत खेती के बताए फायदे

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

सिरोही. शिवगंज ब्लॉक की ग्राम पंचायत जोगापुरा में कृषि कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस मौके पर कृषि, उद्यानिकी, कृषि विज्ञान केंद्र और पशु पालन विभाग के अधिकारियों, वैज्ञानिकों ने खेती व पशुपालन के विभिन्न क्षेत्रों की तकनीकी जानकारियां दी गई। डॉ. हीर सिंह परियोजना निदेशक आत्मा ने कृषक पुरस्कार योजना, डॉ. शिवलाल नोंगिया पशु चिकित्सक ने पशुओं में समयबद्ध टीकाकरण, डॉ. पन्ना लाल चौधरी सहायक निदेशक कृषि सिरोही ने वर्षा जल के संरक्षण कर फार्म पौंड अनुदान पर निर्मित करने, पवन कुमार बरडिया सहायक निदेशक कृषि ने खेती में अनुदानित तारबंदी एवं पाइपलाइन योजना के बारे में बताया। डॉ. जितेंद्र सिंह ने सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिए जाने की कड़ी में वर्मी कंपोस्ट इकाई निर्माण पर पचास हजार के अनुदान की योजना से अवगत कराया। वहीं अवतार सिंह प्रगतिशील कृषक ने जैविक खेती के बारे में बताया। सोनू सहायक कृषि अधिकारी ने क्षेत्र में लग रहे नींबू ,अनार और अमरूद के बगीचों के संधारण एवं देखभाल की जानकारी दी। कृषि विज्ञान केंद्र के एस आर एफ डॉ. महेंद्र सिंह राठौड़ ने कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित कृषक प्रशिक्षण एवं नर्सरी में उपलब्ध पौधों की जानकारी दी।

सभी किसानों भाईयों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, कृष्णा जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं

उपरला ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड उपरला

(किसानों, ग्रामीणों एवं सहकारिता को समर्पित एक प्रगतिशील सहकारी सोसाइटी)

शैतानसिंह अध्यक्ष
भंवराराम उपाध्यक्ष
गोगेन्द्र चौधरी व्यवस्थापक

पूर्णतः कंप्यूटरीकृत एवं सीसीटीवी कैमरों से सुसज्जित प्रगतिशील सहकारी सोसाइटी

सदस्यों एवं किसानों से अपील
देय तिथि पर अल्पकालीन फसली ऋण का चुकारा कर डिफॉल्टर होने से बचें और सीजनली ब्याज मुक्त सहकारी ऋण प्राप्त करने के पात्र बनें

हमारी सेवाएं ; अल्पावधि फसली सहकारी ऋण, भूमि की उपलब्धता के आधार पर स्वीकृत साख सीमा के तहत बायोमेट्रिक पद्धति से वितरित

15 माह से नहीं मिला वेतन, सहकारी समिति के कर्मचारियों ने दिया ज्ञापन

झालावाड़ । अकलेरा कस्बे की सहकारी साख व्यवस्थापक यूनियन शाखा के कर्मचारियों ने ग्रामीण सहकारी बैंक की शाखा प्रबंधक हिमांगनी शर्मा और एसडीएम को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कर्मचारियों का बकाया भुगतान करने की मांग की गई। झालावाड़ केंद्रीय सहकारी बैंक की शाखा अकलेरा के कार्य क्षेत्र में 24 ग्राम सेवा सहकारी समितियां संचालित है। जो केन्द्र एवं राज्य सरकार की अति महत्वपूर्ण योजना किसान फसली ऋण और अन्य योजनाओं को किसानों को घर घर पहुंचाने का काम करती है। लेकिन इन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को वेतन मिले हुए 15 से 18 माह हो गए है।

इस वर्ष 5 लाख नए कृषकों को ऋण उपलब्ध करवाने का लक्ष्य - सहकारिता राज्यमंत्री

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर,। सहकारिता राज्यमंत्री श्री गौतम कुमार ने विधानसभा में कहा कि प्रदेश के जरूरतमंद किसानों को साख सीमा के अनुरूप अधिकतम ऋण उपलब्ध करवाने के पूरे प्रयास किये जाएंगे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष 5 लाख नए कृषकों को ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। सहकारिता राज्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023-24 में केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 10 हजार 162 किसानों को 5704.72 लाख रुपए एवं चूरू जिले में 8 6 हजार 853 किसानों को 4639. 66 लाख रुपए का अल्पकालीन ऋण वितरित किया गया है। उन्होंने जानकारी दी कि चूरू जिले तथा रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में गत चार सालों में मध्यकालीन ऋण के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि मध्यकालीन ऋण के आवेदन प्राप्त होने पर ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।

विधानसभा में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक

सहकारिता मंत्री ने विधानसभा में कहा

व्यवस्थापकों को नियमित करने का मामला वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन

न्यायालय द्वारा इस मामले में दिये गए स्टे के हटने के बाद ही लिया जा सकेगा फैसला

सहकारी बैंकों के पास सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत साख सीमा को वर्तमान में बढाया जाना विचाराधीन नहीं

श्री गौतम कुमार ने कहा कि व्यवस्थापकों को नियमित करने का मामला वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय द्वारा इस मामले में दिये गए स्टे के हटने के बाद ही इस संबंध में फैसला लिया जा सकेगा। इससे पहले विधायक श्री पूसाराम गोदारा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में सहकारिता राज्यमंत्री ने बताया कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को 1.50 लाख रूपये तक अल्पकालीन ऋण की साख सीमा एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा सीधे किसानों को कृषक मित्र योजनान्तर्गत 3.00 लाख रूपये तक अल्पकालीन साख सीमा दिये जाने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि मध्यकालीन ऋण अन्तर्गत केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को 10 लाख रूपये तक की साख सीमा उपलब्ध करायी जाती है। सहकारिता राज्यमंत्री ने बताया कि सहकारी बैंकों के पास सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत उक्त साख सीमा को वर्तमान में बढाया जाना विचाराधीन नहीं है।

उन्होंने बताया कि सहकारी समितियों में लंबे समय से कार्यरत व्यवस्थापकों को नियमित करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उन्होंने रतनगढ विधान सभा क्षेत्र एवं चूरू जिले में केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा विगत 4 वर्ष में किसानों को उक्त साख सीमा अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये ऋणों का विवरण सदन के पटल पर रखा।

सभी किसानों भाईयों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, कृष्णा जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं

उम्मेदाबाद ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड उम्मेदाबाद

पंचायत समिति - जालोर, जिला - जालोर

नगेन्द्र कुमार गुर्रासा - अध्यक्ष
मधुसुदन शर्मा व्यवस्थापक

पूर्णतः कंप्यूटरीकृत सीसीटीवी कैमरों से सुसज्जित एवं किसानों, ग्रामीणों सहकारिता को समर्पित एक प्रगतिशील सहकारी सोसाइटी

अपील ; समय पर फसली ऋण का चुकारा कर, आगामी फसल के लिए ब्याज मुक्त ऋण सुविधा का निरंतर लाभ प्राप्त करें। सोसाइटी और बैंक की प्रगति में भागीदार बनें।

हमारी सेवाएं ■ अल्पकालीन सहकारी फसली ऋण वितरण ■ कृषि जिंस भंडारण ■ समर्थन मूल्य पर कृषि जिंसों की खरीद ■ कृषि यंत्रीकरण ■ कृषि आदान ■ पीडीएस

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

अपना धन अपना बैंक अपना जिला

दी जालोर सैण्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
जालोर, शाखा - अरणाय, जिला - सांचौर

- आवास ऋण
- व्यक्तिगत ऋण
- डेयरी ऋण
- वाहन ऋण
- स्वयं सहायता समूह ऋण
- सहकार किसान कल्याण ऋण
- कम्पोकजट/इन्टीग्रेटेड ऋण
- कृषक मित्र
- किसान सबल योजना

अटूट रिश्ता विश्वास का
हर आवश्यकताओं के अनुरुप जमा व ऋण योजनाएं, जीवन बनाएं बेहतर सभी प्रकार के कृषि व अकृषि ऋण

श्री ओमपालसिंह भाटी - प्रबन्ध निदेशक
श्री दीपक कुमार - प्रबंधक, प्रवीण कुमार - बैकिंग सहायक

अधिक जानकारी हेतु हमारी शाखा में संपर्क करें

स्वत्वाधिकारी, स्वामी, प्रकाशक, संपादक एवं मुद्रक प्रकाश वैष्णव द्वारा वैष्णव कंप्यूटर्स प्रिन्टर्स, वैष्णव फार्म परावा 343041 जिला-सांचौर (राज.) से मुद्रित एवं सुभाष नगर सांचौर से प्रकाशित । संपादक । मो. 9602473302 । नोट : पीआरबी एक्ट के तहत खबर चयन के लिए उत्तरदायी । (तमाम विवादों का न्याय क्षेत्र सांचौर (राज.) होगा)

समाचार संकलन में यद्यपि पूर्ण विश्वसनीयता बरती जाती है तथापि तकनीकी त्रुटियां व अन्य किसी कारणवश समाचार प्रकाशन में त्रुटि होना संभावित है। इस प्रकार की त्रुटि के लिए प्रबन्धन पाक्षिक "मारवाड़ का मित्र" किसी भी प्रकार से जिमेदार नहीं होगा । समाचार पत्र के प्रकाशन की तिथि से एक माह के भीतर ही प्राप्त होने वाली प्रकाशन संबंधी शिकायत/आपत्ती पर विचार होगा एक माह बाद शिकायत आपत्ती पूर्णतया अस्वीकार अमान्य होगी। इस समाचार पत्र से संबंधित समस्त वाद-विवादों का न्यायिक क्षेत्र सांचौर (राज.) रहेगा ।